भारतीय विधि रिपोर्ट

माननीय* आर. *एस. मोंगिया जे. के समक्ष

मेसर्स ज्योति वीडियो थिएटर, जींद, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -उत्तरदाता।

***Civil Writ Petition No.* 8982 of 1989**

7 मई, 1991

(1) *पंजाब* सिनेमा विनियमन, *अधिनियम, 1952 हरियाणा में लागू - पंजाब* सिनेमा *(विनियमन)* नियम, *1952*- नियम. *3 (iv)- पंजाब मनोरंजन शुल्क* अधिनियम, *1955-31 मार्च, 1989 को प्रतिस्थापित हरियाणा अधिनियम* 3 *द्वारा* संशोधित *धारा 3-ए - पंजाब मनोरंजन शुल्क* नियम, 1956-धारा 8-ए -'सिनेमेटोग्राफ' *शब्द की परिभाषा* में *वी.* सी. *आर. शामिल है - अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता, अनिवार्य* है -इस *तरह के लाइसेंस के अनुदान के लिए कठोर आवश्यकताएं, हालांकि, बहिष्कृत - मनोरंजन शुल्क के उद्देश्यों के लिए नियमित सिनेमाघरों. और वी. सी. आर के लिए अपनाए गए विभिन्न मानदंड कानूनी हैं।*

अभिनिर्धारित किया गया कि मनोरंजन शुल्क अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम केवल विभिन्न प्रकार के मनोरंजन पर लगाए जाने वाले मनोरंजन शुल्क से संबंधित हैं।'वी. सी. आर.' एक 'सिनेमेटोग्राफ' है या नहीं, यह 1952 के अधिनियम के तहत देखा जाना चाहिए और उपरोक्त मामले में खण्ड पीठ सही निष्कर्ष निकाला था कि वी. सी. आर. एक सिनेमेटोग्राफ है और 1952 के अधिनियम के तहत उक्त शब्द की परिभाषा के भीतर आता है। विभिन्न प्रकार के सिनेमेटोग्राफ पर विभिन्न प्रकार के शुल्क हो सकते हैं और जहां तक मनोरंजन शुल्क अधिनियम में धारा 3-ए और मनोरंजन शुल्क नियमों में नियम 8-ए को शामिल करके मनोरंजन शुल्क लगाने का संबंध है, तो वी. सी. आर. के लिए अलग *मानदंड* रखने में कुछ भी गलत नहीं था।नतीजतन, मुझे विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि वीडियो पार्लर 1952 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन नहीं हो सकते हैं या उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 9)

यह भी कहा गया कि 1952 के नियमों के भाग III के साथ पठित नियम 3 (ii) में उल्लिखित नियमित सिनेमा के लिए लाइसेंस देने की शर्तें बहुत कठोर हैं और लाइसेंस देने के लिए वही मापदंड वीडियो पार्लरों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो नियमित सिनेमा से छोटे हैं और सस्ते मनोरंजन प्रदान करने के साधन हैं।यह अनुज्ञप्ति प्राधिकरण के लिए होगा कि वह नियमों को इस तरह से लागू करे कि वीडियो पार्लरों को अनुज्ञप्ति से वंचित न किया जाए क्योंकि वे सभी नियमों को पूरा नहीं कर सकते है । 1952 के नियमों के नियम 3 (iv) को ध्यान में रखते हुए इस मामले में याचिकाकर्ता को भविष्य के लिए लाइसेंस प्रदान करना इस रिट याचिका में इस आदेश को चुनौती देने का एक अतिरिक्त आधार है।

(3) पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (इसके बाद मनोरंजन शुल्क अधिनियम के रूप में संदर्भित) के रूप में जाना जाने वाला एक अधिनियम है, जो हरियाणा राज्य में भी लागू होता है, जिसके तहत राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के मनोरंजन पर शुल्क लगाने के लिए अधिकृत है।1955 के अधिनियम के तहत, पूर्ववर्ती पंजाब राज्य ने पंजाब मनोरंजन शुल्क नियम, 1956 के रूप में जाने जाने वाले नियम बनाए थे, जो हरियाणा राज्य पर भी लागू होते हैं (जिसे इसके बाद मनोरंजन शुल्क नियम कहा जाता है)।हरियाणा राज्य द्वारा समय-समय पर इन नियमों में संशोधन किया गया है।वर्ष 1984 में, 1984 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा, खंड 3-ए को मनोरंजन शुल्क अधिनियम में जोड़ा गया था। 1984 में शुरू की गई खंड 3-ए निम्नानुसार हैः -

> "3ए. ***वीडियो शो पर शुल्क***—*इस* अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, भुगतान पर शो प्रदर्शित करने वाले वीडियो सेट का मालिक प्रति वर्ष एक लाख रुपये की राशि से अधिक की दर से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे सरकार उस क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकती है जहां वीडियो सेट प्रदर्शनी के लिए स्थापित किया गया है।शुल्क का भुगतान निर्धारित तरीके से पहले से किया जाएगा।"

(4) 29 जून, 1984 को हरियाणा राज्य ने आबकारी और कराधान विभाग में मनोरंजन शुल्क अधिनियम की खंड 3-ए के साथ पठित खंड 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोरंजन शुल्क नियमों में संशोधन किया और उक्त नियमों में नियम 8-ए जोड़ा गया। नियम 8-ए निम्नानुसार हैः—

एस-ए। ***वीडियो शो पर शुल्क का भुगतान।—(1)*** हरियाणा राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर भुगतान पर वीडियो शो प्रदर्शित करने वाले वीडियो सेट का स्वामी संबंधित जिले के मनोरंजन कर अधिकारी प्रभारी को फॉर्म पी. ई. डी.-I में आवेदन करेगा और उसके द्वारा देय शुल्क के बराबर राशि को प्रतिभूति के रूप में कोषागार में जमा करेगा और अपने आवेदन के साथ जमा राशि दिखाने वाली कोषागार रसीद संलग्न करेगा।

(2) <u>प्रतिभूति</u> के अलावा, मालिक निम्नलिखित स्लैब दरों पर अग्रिम तिमाही में मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगाः—

जनसंख्या वाले शहर/कस्बा/गाँव में स्थित परिसरों के लिए	प्रति तिमाही देय शुल्क की दर।
((i) 10,000 से कम	रु. 10, 000.00
((ii) 10,000 से 24,999 तक	रु. 15, 000.00
(iii) 25,000 से ऊपर	रु. 25, 000.00

व्याख्याःवर्ष 1981 की जनगणना के आंकड़े किसी भी स्थान की जनसंख्या निर्धारित करने का आधार होंगे।

(3) मनोरंजन शुल्क पहले काम पर देय होगा। उस तिमाही से पहले के महीने का दिन जिससे यह संबंधित है। मनोरंजन शुल्क की जमा राशि दिखाने वाली कोषागार रसीद स्वामी द्वारा संबंधित मनोरंजन कर अधिकारी को ऐसे महीने के अगले कार्य दिवस पर प्रस्तुत की जाएगी।

(4) उप-पैरा (3) में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में स्वामी के विफल रहने की स्थिति में जिले का प्रभारी मनोरंजन कर अधिकारी प्रतिभूति का पूरा या कुछ हिस्सा जब्त करने में सक्षम होगा।

(5) यदि मालिक मनोरंजन बंद करने का इरादा रखता है, तो वह जिले के प्रभारी मनोरंजन कर अधिकारी को लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देगा।"

(6) यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1989 के हरियाणा अधिनियम संख्या 3 द्वारा, मनोरंजन शुल्क अधिनियम की खंड 3-ए को 17 मार्च, 1989 से एक नई खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो निम्नानुसार हैः—

"3-ए. ***वीडियो शो पर शुल्क*** *—(1)* इस अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक सौ से कम व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले भुगतान पर शो प्रदर्शित करने वाले वीडियो सेट का मालिक प्रति वर्ष दो लाख रुपये से अधिक की दर से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वी. सी. आर. द्वारा से उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में, एक नियमित सिनेमा चलाने के लिए लाइसेंस देने की शर्तें बहुत सख्त थीं और वीडियो पार्लरों पर लागू नहीं की जा सकती थीं, जो छोटे स्तर के प्रतिष्ठान थे जो समाज के अपेक्षाकृत निचले स्तर के लोगों को सस्ती दरों पर मनोरंजन प्रदान करते थे। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि एक बार मनोरंजन शुल्क अधिनियम में वर्ष 1989 में खंड 3-ए के प्रतिस्थापन द्वारा, बैठने की क्षमता को मनोरंजन शुल्क लगाने का आधार बना दिया गया था, शहर या गांव की आबादी जहां वीडियो पार्लर स्थित था, उसका कोई असर नहीं था, और इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 1989 को प्रतिस्थापित मनोरंजन शुल्क नियमों का नियम 8-ए मनमाना था और इसे रद्द किया जा सकता था। 1989 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8982 से संबंधित अतिरिक्त मुद्दा भी उठाया गया था, जिसका संदर्भ बाद में दिया जाएगा।

(7) जहां तक पहले बिंदु का संबंध है, कि 'वी. सी. आर.' एक 'सिनेमेटोग्राफ' है या नहीं, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि यह बिंदु उनके खिलाफ **मैसर्स दीप स्नैक बार, सोनीपत और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और *अन्य***[1] *मामले में इस अदालत की* एक *खण्ड पीठ के फैसले में* शामिल है। खण्ड पीठ ने इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या 'वी. सी. आर.' को 'सिनेमेटोग्राफ' की परिभाषा में शामिल किया गया है, जैसा कि 1952 के अधिनियम में दिया गया हैः—

> "हमने तर्क पर विधिवत विचार किया है लेकिन इसे प्रतिग्रहण करना करने में अपनी असमर्थता पर खेद है। हरियाणा अधिनियम में 'फिल्म' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे केंद्रीय अधिनियम में परिभाषित किया गया है, हालांकि, हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, केंद्रीय अधिनियम से इसकी परिभाषा को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। खंड 2 के क्ल. (ए) ने 'सिनेमेटोग्राफ' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया हैः—

(क) 'सिनेमेटोग्राफ' में गतिशील चित्रों या चित्रों की श्रृंखला के प्रतिनिधित्व के लिए कोई भी उपकरण शामिल है। 'सिनेमेटोग्राफ' शब्द की परिभाषा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह एक समावेशी परिभाषा है न कि एक संपूर्ण परिभाषा। यह आगे स्पष्ट है कि जिस यंत्र या यंत्र से चलचित्रों को दर्शाया जाता है, उसे सिनेमेटोग्राफ कहा जा सकता है। परिभाषा फिल्म की बात नहीं करती है और इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिनिधित्व फिल्म से होना चाहिए। यह कैसेट सहित किसी भी चीज़ से हो सकता है। वी. सी. आर. जैसे प्रोजेक्टर का उपयोग चलचित्रों के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है, हालांकि दोनों में प्रतिनिधित्व के लिए तकनीक अलग-अलग है। हालाँकि, परिभाषा उस तकनीक को ध्यान में नहीं रखती है जिसके द्वारा चलती तस्वीरों को दर्शाया जाता है। वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में विधानमंडल को यह जानने के लिए माना जाता है कि परिभाषा को विस्तारित अर्थ दिया जा सकता है। इसलिए, परिभाषा में उपकरण शब्द के अर्थ को एक प्रोजेक्टर तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है जिसके द्वारा एक फ़ाइल की जांच की जाती है। नतीजतन, हमारी राय है कि वी. सी. आर. को 'सिनेमेटोग्राफ' शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया है।"

(8) हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मनोरंजन शुल्क अधिनियम के संशोधन को देखते हुए, जिसके द्वारा हरियाणा राज्य द्वारा वर्ष 1984 में खंड 3-ए को जोड़ा गया था और 1956 के मनोरंजन शुल्क नियमों में नियम 8-ए को भी शामिल किया गया था, विधानमंडल का इरादा वी. सी. आर. को सिनेमेटोग्राफ से अलग व्यवहार करना था,

[1] A.I.R.1984 Punjab and Haryana 377.

क्योंकि वी. सी. आर. एक सिनेमेटोग्राफ नहीं था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यदि मनोरंजन शुल्क अधिनियम में खंड 3-ए और मनोरंजन शुल्क नियमों में नियम 8-ए को लागू करने वाली यह अधिसूचना पहले होती, तो उपरोक्त मामले में खण्ड पीठ का निर्णय अलग होता। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने मनोरंजन शुल्क लगाने के उद्देश्य से सिनेमेटोग्राफ के बड़े वर्ग से वीडियो प्रदर्शनी लेने के लिए हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम में वीडियो प्रदर्शनी को अलग से परिभाषित किया है और वीडियो पार्लरों को लाइसेंस देने के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। उनके अनुसार, इससे पता चलता है कि इस बात को लेकर विवाद है कि वी. सी. आर. एक सिनेमेटोग्राफ है या नहीं।

(9) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं है। मनोरंजन शुल्क अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम केवल विभिन्न प्रकार के मनोरंजन पर लगाए जाने वाले मनोरंजन शुल्क से संबंधित हैं। 'वी. सी. आर.' एक 'सिनेमेटोग्राफ' है या नहीं, यह 1952 के अधिनियम के तहत देखा जाना चाहिए और उपरोक्त मामले में खण्ड पीठ सही निष्कर्ष निकाला था कि वी. सी. आर. एक सिनेमेटोग्राफ है और 1952 के अधिनियम के तहत उक्त शब्द की परिभाषा के भीतर आता है। विभिन्न प्रकार के सिनेमेटोग्राफ पर विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हो सकते हैं।

और मनोरंजन शुल्क अधिनियम में खंड जे. ए. और मनोरंजन शुल्क नियमों में नियम 8-ए को शामिल करके वी. सी. आर. के लिए एक अलग यार्ड-स्टिक रखने में गलत था। यह सटीक रूप से हिमाचल प्रदेश में किया गया था, जैसा कि **प्रकाश चंद मंडी और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य** [2] में रिपोर्ट किए गए फैसले *से स्पष्ट है। वहाँ नियमित सिनेमाघरों* ने *इस बात पर आपत्ति* जताई थी कि वीडियो पार्लरों से उनकी तुलना में कम शुल्क क्यों लिया जा रहा है, हालाँकि वीडियो पार्लर भी सिनेमेटोग्राफ थे। इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि मनोरंजन कर्तव्य के उद्देश्य से अलग से वीडियो प्रदर्शनी को परिभाषित करना पूरी तरह से कानूनी है। हाथ में मामले में, वीडियो पार्लरों को मनोरंजन शुल्क अधिनियम और नियमों में क्रमशः खंड 3-ए और नियम 8-ए को शामिल करके मनोरंजन कर्तव्य के उद्देश्य से नियमित सिनेमा की तुलना में अलग व्यवहार किया गया है। नतीजतन, मुझे विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि वीडियो पार्लर को 1952 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन नहीं किया जा सकता है या उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(10) मैं यहां इस मुद्दे पर चर्चा कर सकता हूं कि 1952 के नियमों के भाग III के साथ पठित नियम 3 (यू) में उल्लिखित नियमित सिनेमा के लिए लाइसेंस देने की शर्तें बहुत कठोर

[2] ALR. 1984 H.P. 47

और कठोर हैं और लाइसेंस देने के लिए वही मापदंड वीडियो पार्लरों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो नियमित सिनेमा से छोटे हैं और सस्ते मनोरंजन प्रदान करने के साधन हैं। 1952 के नियमों के भाग III में, लाइसेंस देने के लिए विचार करने से पहले सिनेमा हाउस के निर्माण के लिए स्पष्ट रूप से बहुत सख्त आवश्यकताएं हैं। वीडियो पार्लर में भाग एच. आई. में उल्लिखित सभी उपायों को लागू करना वास्तव में बहुत कठोर होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार और मुझे बताया गया है कि कुछ अन्य राज्य सरकारें वीडियो पार्लरों के लिए लाइसेंस देने के लिए विशेष नियम बनाने के लिए आगे आई हैं। जब 1952 के अधिनियम और उसके तहत नियम बनाए गए थे, तो फिल्मों की प्रदर्शनी में तकनीकी प्रगति की कल्पना शायद नहीं की जा सकी थी। यह राज्य सरकार और उसके विधानमंडलों का दायित्व होगा कि वे तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के साथ विधायी क्षेत्र में गति बनाए रखें और वीडियो पार्लरों को लाइसेंस देने के लिए एक उचित कानून बनाएँ। जब तक विधानमंडल कानून में संशोधन नहीं करता है, तब तक मेरे लिए यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल होगा कि वीडियो पार्लरों के लिए लाइसेंस देने के लिए क्या मानदंड होने चाहिए। यह अनुज्ञप्ति प्राधिकरण पर होगा कि वह नियमों को इस तरह से लागू करे कि वीडियो पार्लरों को अनुज्ञप्ति से वंचित न किया जाए क्योंकि वे 1952 के नियमों द्वारा परिकल्पित सिनेमा के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1989 के मनोरंजन शुल्क अधिनियम की खंड 3-ए और मनोरंजन शुल्क नियमों के नियम 8-ए के प्रतिस्थापन से पहले, देय मनोरंजन शुल्क उस गांव/शहर की आबादी के आधार पर था जहां वीडियो पार्लर स्थित था, चाहे वीडियो पार्लर की सीटों की संख्या कुछ भी हो। उपर्युक्त खंड और नियम के प्रतिस्थापन के बाद, यह प्रावधान किया गया था कि 99 सीटों तक की क्षमता वाले वीडियो पार्लरों से उस शहर/गांव की आबादी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा जहां ऐसा वीडियो पार्लर स्थित है और जहां तक 100 या उससे अधिक सीटों वाले वीडियो पार्लर का संबंध है, मनोरंजन शुल्क एक नियमित सिनेमा द्वारा भुगतान किए गए शुल्क के बराबर होगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। तर्क आगे बढ़े कि एक बार मनोरंजन शुल्क लगाने के लिए सीट्स की संख्या को आधार बना दिया गया है, तो विशेष आबादी वाले शहर या गांव में वीडियो पार्लर का स्थान अर्थहीन हो जाना चाहिए। वकील के अनुसार, 99 सीटों तक की बैठने की क्षमता वाले सभी वीडियो पार्लरों पर, विशेष आबादी वाले शहर या गांव में उनके स्थान को दर्शाते हुए, उसी दर से मनोरंजन शुल्क लगाया जाना चाहिए और देय शुल्क वही होना चाहिए जो 10,000 से कम आबादी वाले शहर या गांव में स्थित वीडियो पार्लर से लिया जाता है।

(12) मुझे इस प्रस्तुति में भी कोई योग्यता नहीं मिलती है। मनोरंजन शुल्क एक से अधिक आधार पर भी हो सकता है। 100 से अधिक सीटों वाले वीडियो पार्लर को नियमित सिनेमा के

बराबर माना जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप, मनोरंजन के उद्देश्य से इस तरह के वीडियो पार्लर को नियमित सिनेमा के बराबर मानने में कुछ भी गलत नहीं है।यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आम तौर पर 10,000 से कम आबादी वाले गाँव या शहर में 100 से अधिक सीटों वाले वीडियो पार्लर का निर्माण नहीं किया जाएगा।25, 000 या उससे अधिक की आबादी वाले शहर या गाँव में स्थित 100 से अधिक सीटों की क्षमता वाले वीडियो पार्लर की तुलना में 100 से कम सीटों वाला वीडियो पार्लर सस्ता होगा।उत्तरार्द्ध से निश्चित रूप से अधिक लोगों का मनोरंजन करने और 10,000 से कम आबादी वाले शहर या गांव में स्थित वीडियो पार्लर की तुलना में अधिक ग्राहक होने की उम्मीद की जाएगी।तो एक 99 सीटों वाला वीडियो पार्लर और एक वीडियो पार्लर जिसमें इससे अधिक सीटें है दो अलग-अलग वर्ग हैं और इन्हें अलग-अलग तरीके से देखा जा सकता है।विशेष आबादी वाले शहर या गाँव में वीडियो पार्लर के स्थान का शुल्क की मात्रा के साथ सीधा संबंध है।

(13) 1989 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8982 में एक अतिरिक्त मुद्दा उठाया गया था कि 1952 के नियमों के नियम 3 (iv) के आधार पर एक अस्थायी लाइसेंस से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी इस आधार पर कि चूंकि पहले से ही एक स्थायी सिनेमा अस्तित्व में है, इसलिए कोई अस्थायी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।तर्क यह था कि 1952 के नियमों के नियम 3 (iv) को *इस न्यायालय की* एकल *पीठ ने* ***रासदेव टूरिंग टॉकीज़*** **बनाम जिला मजिस्ट्रेट, कमल और एक अन्य**[3] मामले में खारिज कर दिया है।1952 के नियमों के नियम 3 (iv) को निरस्त करने से पहले, नीचे पढ़ा गया थाः—

> "3((iv) जहाँ स्थायी सिनेमा है, वहाँ टूरिंग सिनेमेटोग्राफ को कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगाः
>
> बशर्ते कि ऐसा लाइसेंस ऐसे स्थान के लिए कुल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए, मेले और धार्मिक समारोहों जैसे विशेष अवसरों पर या किसी विशेष अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया जा सकता है।
>
> ***व्याख्याः***—*इस* उप-नियम के उद्देश्य के लिए 'स्थान' शब्द का अर्थ उस गाँव या शहर की क्षेत्रीय सीमाओं के दो मील के भीतर का क्षेत्र होगा जिसमें एक स्थायी सिनेमा स्थित है।
>
> यदि किसी भवन में टूरिंग सिनेमेटोग्राफ लगाने का प्रस्ताव है, तो पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियम, 1952 के भाग III में नियमों के प्रावधानों का लाइसेंसधारियों

द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।"

जब उपरोक्त नियम **रासदीप टूरिंग टॉकीज** मामले (उपरोक्त) में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष *विचार के लिए आया* था, तो न्यायाधीश द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि केवल इसलिए कि एक विशेष स्थान पर एक स्थायी सिनेमा स्थापित किया गया था, एक अस्थायी लाइसेंस कभी भी नहीं दिया जा सकता था, पूरी तरह से मनमाना प्रतीत होता है, और इसलिए, इसे रद्द कर दिया गया था।तथापि, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

"यह नियम वैध होता यदि यह केवल नियम 3 (i) के तहत लाइसेंस देने या अस्वीकार करने में (3) ए. आई. आर. 1967 पंजाब 219 का प्रावधान करता।

जिला मजिस्ट्रेट उस स्थान पर उपलब्ध स्थायी सिनेमेटोग्राफ प्रदर्शनी सुविधाओं की संख्या को देखते हुए किसी विशेष अवधि के दौरान किसी विशेष स्थान पर पर्यटन सिनेमा के प्रावधान की आवश्यकता को ध्यान में रखेंगे।यदि नियम 3 (iv) में निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक परंतुक जोड़ा गया होता तो मैं भी विवादित नियम को बनाए रखताः

बशर्ते कि यह प्रतिबंध किसी विशेष स्थान पर बड़ी संख्या में अस्थायी आगंतुकों के आने के कारण 4 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी आवश्यकता के मामले में लागू नहीं होगा।"

रासदीप *टूरिंग टॉकीज के मामले* (उपरोक्त) के बाद, 1952 के नियमों के नियम 3 (iv) को विद्वान एकल न्यायाधीश के सुझाव के अनुरूप लाने के लिए संशोधित किया गया था, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।1952 के नियमों का संशोधित नियम 3 (iv) इस प्रकार हैः—

"3((iv) जहाँ स्थायी सिनेमा है, वहाँ टूरिंग सिनेमेटोग्राफ को कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसा लाइसेंस ऐसे स्थान के लिए कुल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए, विशेष अवसरों जैसे कि मेले और धार्मिक समारोहों पर या किसी विशेष अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया जा सकता है।"

(14) मामले के इस दृष्टिकोण में, मैंने पाया कि याचिकाकर्ता को अस्थायी लाइसेंस से इनकार करने में अधिकारियों को उचित ठहराया गया था क्योंकि विचाराधीन शहर में पहले से ही एक स्थायी सिनेमा मौजूद है।यदि और जब याचिकाकर्ता स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन

करता है, तो इस निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(15) पूर्वगामी कारणों से, मुझे इन रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिन्हें खारिज कर दिया जाता है।हालांकि, मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि अधिकारी 1952 के अधिनियम और 1952 के नियमों के तहत वीडियो पार्लर को अस्थायी/स्थायी लाइसेंस देते समय निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

<u>अस्वीकरण</u> : **स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा** ।

विनीत कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा